मुख्य परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था के प्रश्न

1. भारतीय और बिहार अर्थव्यवस्था का वर्तमान परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था:

1. भारतीय अर्थव्यवस्था पर COVID-19 महामारी के प्रभाव का विश्लेषण करें और इसके प्रभावों को कम करने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा करें। महामारी के बाद के युग में आर्थिक सुधार के लिए प्रमुख चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं?
2. सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने में सरकार की हालिया आर्थिक नीतियों जैसे पीएलआई योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इन नीतियों से जुड़ी चिंताएँ और संभावित समाधान क्या हैं?
3. भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें। जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और इससे जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।
4. चीन और वियतनाम जैसे प्रमुख एशियाई साथियों के साथ भारत के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करें और तुलना करें। भारत के भविष्य के आर्थिक विकास के लिए सीखे गए सबक और नीतिगत निहितार्थ क्या हैं?
5. भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका का विश्लेषण करें। देश में एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक चुनौतियों और नीतिगत उपायों पर चर्चा करें।
6. राजकोषीय और मौद्रिक नीति की अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में उनकी भूमिका की व्याख्या करें। व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में आरबीआई और सरकार के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा करें।
7. रूस-यूक्रेन युद्ध और बढ़ती मुद्रास्फीति जैसे वैश्विक कारकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण करें। वैश्विक अनिश्चितताओं के सामने आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए संभावित जोखिम और शमन रणनीतियाँ क्या हैं?

बिहार की अर्थव्यवस्था:

8. बिहार की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और हाल के वर्षों में इसकी प्रगति का मूल्यांकन करें। राज्य की आर्थिक विकास रणनीति की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं कमियाँ क्या हैं?
9. बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।
10. आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में बिहार के गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, पर्यटन और आईटी की क्षमता की जांच करें। निवेश आकर्षित करने और इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किन विशिष्ट पहलों की आवश्यकता है?
11. बिहार के आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे की बाधाओं, कौशल अंतराल और खराब प्रशासन से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। इन चुनौतियों से निपटने और आर्थिक विकास के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने के लिए ठोस उपाय सुझाएं।
12. भारत के अन्य राज्यों के साथ बिहार के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करें और तुलना करें। इन तुलनाओं से क्या सबक सीखे गए हैं और बिहार अपनी आर्थिक रैंकिंग में सुधार करने के लिए अपनी ताकत का लाभ कैसे उठा सकता है और अपनी कमजोरियों को कैसे दूर कर सकता है?
13. बिहार में लोगों के जीवन पर केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएमजेडीवाई और उज्ज्वला योजना जैसी पहलों के प्रभाव का विश्लेषण करें। राज्य में समावेशी आर्थिक विकास और गरीबी में कमी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय सुझाएं।
14. बिहार के आर्थिक विकास में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका पर चर्चा करें। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोग क्या हैं?

❑❑❑

2. भारत और बिहार में कृषि और संबद्ध क्षेत्र

भारत:

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के महत्व का विश्लेषण करें, जीडीपी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा में उनके योगदान पर प्रकाश डालें।
2. भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के दीर्घकालिक प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, स्थिरता, पर्यावरणीय प्रभाव और किसान कल्याण के संदर्भ में इसकी सफलताओं और चुनौतियों का समाधान करें।
3. भारतीय कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें, जिनमें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, मिट्टी का क्षरण और बाजार पहुंच के मुद्दे शामिल हैं। इन चुनौतियों पर काबू पाने और सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियाँ सुझाएँ।
4. भारतीय कृषि को बदलने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका का परीक्षण करें। उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और संसाधन उपयोग में सुधार लाने में सटीक कृषि, ड्रोन और अन्य प्रौद्योगिकियों की क्षमता पर चर्चा करें।
5. किसानों को समर्थन देने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कृषि बीमा योजनाओं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
6. चीन, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अन्य प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के कृषि प्रदर्शन की तुलना करें और तुलना करें। भारत के लिए सुधार के लिए प्रमुख सबक और क्षेत्रों की पहचान करें।
7. कृषि आय में विविधता लाने और ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने में पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे संबद्ध क्षेत्रों के महत्व पर चर्चा करें। इन क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाएं और उनके विकास के लिए रणनीतियां सुझाएं।

बिहार विशिष्ट:

8. बिहार में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें, इसकी ताकत और कमजोरियों पर प्रकाश डालें। राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य की पिछड़ती कृषि उत्पादकता में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें।
9. बिहार में किसानों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों की जाँच करें, जिनमें भूमि विखंडन, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ऋण और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच और बाढ़ और सूखे का प्रभाव शामिल हैं।
10. किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देने में सात निश्चय और कृषि रोड मैप जैसी बिहार सरकार की पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
11. बिहार के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने में लीची, आम और मक्का जैसी विशिष्ट कृषि वस्तुओं की क्षमता पर चर्चा करें।
12. किसानों को सशक्त बनाने और बाजार में उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करने में सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका का विश्लेषण करें। बिहार में उनके आगे के विकास के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें।
13. भूमि स्वामित्व पैटर्न और कृषि उत्पादकता पर बिहार के भूमि सुधारों के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। न्यायसंगत भूमि वितरण सुनिश्चित करने और कुशल भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।
14. कृषि उपज में मूल्य जोड़ने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बिहार में कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता पर चर्चा करें।

❑❑❑

3. कृषि सुधार एवं भूमि सुधार

भारत:

1. भारत में भूमि सुधारों के ऐतिहासिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, उनके इच्छित उद्देश्यों और भूमि स्वामित्व पैटर्न और कृषि उत्पादकता पर उनके वास्तविक प्रभाव पर प्रकाश डालें।
2. भूमि पुनर्वितरण और ग्रामीण असमानता को कम करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम और उसके बाद के भूमि सीमा कानूनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
3. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की प्रमुख विशेषताओं और संभावित लाभों पर चर्चा करें और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें।
4. बाजार पहुंच, प्रतिस्पर्धा और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव की जांच करें।
5. बाजार दक्षता और किसान आय में सुधार में ईएनएएम और एपीएमसी सुधार जैसे कृषि विपणन सुधारों की भूमिका का विश्लेषण करें।
6. किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने में अनुबंध खेती और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की क्षमता पर चर्चा करें।

7. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के पीछे के तर्क और किसानों की आय की रक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
8. टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और किसानों तक नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार में कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं की भूमिका की जांच करें।
9. भारतीय कृषि को बदलने और इसकी दक्षता, उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने में सटीक कृषि, ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता पर चर्चा करें।
10. विभिन्न देशों में भूमि सुधार नीतियों और कृषि विकास मॉडल की तुलना करें और भारत के लिए सीखे गए सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।

बिहार विशिष्ट:

11. बिहार में कार्यान्वित ऐतिहासिक भूमि सुधार पहलों का विश्लेषण करें, भूमि पुनर्वितरण प्राप्त करने और ग्रामीण गरीबी को संबोधित करने में उनकी प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करें।
12. बिहार में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय पर भूमि विखंडन के प्रभाव का मूल्यांकन करें और इस मुद्दे के समाधान के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।
13. बिहार में छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के सामने भूमि, ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुंच सहित चुनौतियों पर चर्चा करें और उन्हें सशक्त बनाने और उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दें।
14. भूमि प्रबंधन प्रथाओं में सुधार, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बिहार में भूमि समेकन और सहकारी खेती की क्षमता की जांच करें।
15. राज्य में कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों के समाधान में बिहार सरकार की सात निश्चय और कृषि रोड मैप जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
16. स्थान-विशिष्ट कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करें।
17. पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कृषि-पारिस्थितिकी खेती और जैविक खेती की क्षमता का विश्लेषण करें।
18. बिहार में भूमि सुधार और कृषि विकास की प्रगति की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें, सुधार के क्षेत्रों और अनुकरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
19. बिहार में कृषि विकास और किसानों की आजीविका में सुधार में योगदान देने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
20. बिहार में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव पर चर्चा करें और लचीलापन बनाने और जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों का सुझाव दें।

❑❑❑

4. कृषि विकास में पहल

भारत:

1. हरित क्रांति की प्रभावशीलता और भारतीय कृषि पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन करें। इसकी सफलताओं, चुनौतियों और दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता पर चर्चा करें।
2. भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) जैसी प्रमुख सरकारी पहलों के उद्देश्यों और उपलब्धियों का विश्लेषण करें।
3. कृषि विकास को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका पर चर्चा करें। ई-एनएएम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और ड्रोन के उपयोग जैसी पहल इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर रही हैं?
4. टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने में जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की क्षमता की जांच करें।
5. बाजार दक्षता और किसान आय में सुधार के लिए एपीएमसी सुधार और अनुबंध खेती जैसे कृषि विपणन सुधारों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
6. सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने में किसान सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण के महत्व का विश्लेषण करें। इसे प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषि विस्तार सेवाओं की क्या भूमिकाएँ हैं?
7. भारतीय कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। विश्लेषण करें कि जलवायु-स्मार्ट कृषि और मौसम-आधारित फसल बीमा जैसी पहल किसानों को अनुकूलन और लचीलापन बनाने में कैसे मदद कर रही हैं।
8. भारत की कृषि विकास रणनीतियों की तुलना अन्य विकासशील देशों से करें। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।

बिहार विशिष्ट:

9. राज्य के सामने आने वाली विशिष्ट कृषि चुनौतियों के समाधान में बिहार सरकार की सात निश्चय और कृषि रोड मैप पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
10. बिहार में कृषि उत्पादकता पर भूमि विखंडन और सीमित सिंचाई सुविधाओं के प्रभाव का विश्लेषण करें। इन मुद्दों के समाधान के लिए रणनीतियाँ सुझाएँ।
11. बिहार के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने में लीची, आम और मक्का जैसी विशिष्ट फसलों की क्षमता पर चर्चा करें।
12. स्थान-विशिष्ट कृषि प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में बिहार में कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका की जांच करें।
13. किसानों को सशक्त बनाने और उनकी बाजार पहुंच में सुधार करने में बिहार की सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
14. बिहार में बाढ़ और सूखे से कृषि के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करें। चर्चा करें कि वाटरशेड प्रबंधन और सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों जैसी पहल इन जोखिमों को कम करने में कैसे मदद कर सकती हैं।
15. बिहार के कृषि प्रदर्शन की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सुधार कर सकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।
16. बिहार में पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में कृषि-पारिस्थितिकी खेती और जैविक खेती की क्षमता पर चर्चा करें।
17. फसल के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क सहित बिहार के कृषि विपणन बुनियादी ढांचे की भूमिका का विश्लेषण करें।
18. कृषि उत्पादकता में सुधार, किसानों को सशक्त बनाने और बिहार में सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतिगत सिफारिशें और पहल सुझाएं।

❑❑❑

5. कृषि सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

भारत:

1. भारत में कृषि सब्सिडी प्रदान करने के पीछे के तर्क का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उनके इच्छित उद्देश्यों, किसानों पर वास्तविक प्रभाव और संभावित आर्थिक विकृतियों पर चर्चा करें।
2. भारत में विभिन्न कृषि सब्सिडी, जैसे उर्वरक सब्सिडी, बिजली सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। उनकी ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करें.
3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की अवधारणा और कृषि क्षेत्र में पारंपरिक सब्सिडी वितरण तंत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने की इसकी क्षमता की व्याख्या करें।
4. भारत में कृषि सब्सिडी के लिए डीबीटी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करें। इसकी उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा करें और इसकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाएं।
5. किसानों की आय, कृषि उत्पादकता और कृषि क्षेत्र की समग्र दक्षता पर डीबीटी के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करें।
6. भारत में कृषि सब्सिडी के लिए डीबीटी के उपयोग की तुलना अन्य देशों से करें। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
7. कृषि सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और समर्थन की अधिक लक्षित और कुशल प्रणाली में परिवर्तन के संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें।
8. कृषि सब्सिडी के वितरण में सुधार और डीबीटी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

बिहार विशिष्ट:

9. बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि सब्सिडी की सीमा और प्रकार का विश्लेषण करें। किसानों और राज्य के कृषि क्षेत्र पर उनके प्रभाव पर चर्चा करें।
10. बिहार में कृषि सब्सिडी के लिए डीबीटी लागू करने में आने वाली चुनौतियों की जांच करें। इनमें डेटा सटीकता, बुनियादी ढांचे की सीमाएं और किसान जागरूकता से संबंधित मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
11. बिहार में कृषि सब्सिडी के लक्ष्यीकरण और दक्षता में सुधार में डीबीटी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। किसानों की आय और कृषि उत्पादकता पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें।
12. बिहार में कृषि सब्सिडी के लिए डीबीटी लागू करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशिष्ट नीतिगत सिफारिशें और पहल सुझाएं।

13. बिहार में कृषि सब्सिडी के लिए डीबीटी के कार्यान्वयन की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सुधार कर सकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।

14. बिहार के सामने आने वाली विशिष्ट कृषि चुनौतियों, जैसे भूमि विखंडन, सीमित सिंचाई सुविधाएं और अपर्याप्त बाजार पहुंच को संबोधित करने में डीबीटी की क्षमता पर चर्चा करें।

15. बिहार में डीबीटी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और कृषि सब्सिडी के कुशल वितरण को बढ़ावा देने में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

16. डीबीटी के माध्यम से कृषि सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए ब्लॉकचेन और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता का विश्लेषण करें।

❑❑❑

6. न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारत:

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारणा और भारतीय कृषि में इसकी भूमिका की व्याख्या करें। किसानों की आय की रक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करें।

2. सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान करने के पीछे के तर्क का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। एमएसपी के पक्ष और विपक्ष में आर्थिक तर्कों और बाजार विकृतियों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें।

3. एमएसपी कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों, जैसे खरीद मुद्दे, भंडारण घाटे और सरकार पर राजकोषीय बोझ की जांच करें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संभावित समाधान सुझाएँ।

4. कृषि विविधीकरण और किसान प्रोत्साहन पर एमएसपी के प्रभाव का विश्लेषण करें। क्या एमएसपी किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है?

5. भारत की एमएसपी नीतियों की तुलना अन्य देशों से करें। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।

6. एमएसपी पर व्यापार उदारीकरण और वैश्वीकरण के संभावित प्रभाव और भारतीय कृषि में इसकी भूमिका पर चर्चा करें।

7. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कमजोर आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

8. पीडीएस के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे लीकेज, लक्ष्यीकरण मुद्दे और सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता का विश्लेषण करें। इसकी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए संभावित सुधारों का सुझाव दें।

9. पीडीएस के लक्ष्यीकरण और प्रबंधन में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता पर चर्चा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।

10. एमएसपी खरीद और पीडीएस संचालन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसकी ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करें और सुधार के लिए सुधारों का सुझाव दें।

बिहार विशिष्ट:

11. बिहार में एमएसपी कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। क्या एमएसपी राज्य के सभी किसानों तक पहुंचता है, और एमएसपी लाभ तक पहुंचने में छोटे और सीमांत किसानों को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

12. बिहार में लीची, आम और मक्का जैसी विशिष्ट फसलों पर एमएसपी के प्रभाव की जांच करें। क्या एमएसपी किसानों को इन फसलों की खेती करने और राज्य के कृषि निर्यात में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है?

13. बिहार में लक्षित आबादी तक पहुंचने और सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने में पीडीएस की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। राज्य में पीडीएस के सामने क्या विशिष्ट चुनौतियाँ हैं?

14. बिहार में एमएसपी और पीडीएस के कार्यान्वयन की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सुधार कर सकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।

15. एमएसपी तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बिहार में एफपीओ और किसान सहकारी समितियों की क्षमता पर चर्चा करें।

16. बिहार में एमएसपी और पीडीएस संचालन की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार में ई-एनएएम और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका का विश्लेषण करें।

17. एमएसपी कार्यान्वयन और पीडीएस प्रभावशीलता पर बिहार की विशिष्ट पहल, जैसे सात निश्चय कार्यक्रम, के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

18. बिहार में एमएसपी और पीडीएस की प्रभावशीलता में सुधार के लिए ठोस नीतिगत सिफारिशें और पहल सुझाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनका लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।

❑❑❑

7. कृषि एवं कृषि विपणन में ई-प्रौद्योगिकी

भारत:

1. कृषि में ई-प्रौद्योगिकी की अवधारणा और इस क्षेत्र में क्रांति लाने की इसकी क्षमता की व्याख्या करें। कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में ई-प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
2. कृषि उत्पादकता, दक्षता और स्थिरता पर ई-प्रौद्योगिकी के प्रभाव का विश्लेषण करें। प्रौद्योगिकी किसानों को बेहतर जानकारीपूर्ण निर्णय लेने और संसाधन उपयोग में सुधार करने में कैसे मदद कर सकती है?
3. किसानों को बाजारों से जोड़ने, आवश्यक जानकारी और सेवाएँ प्रदान करने और कृषि उपज के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करने में डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन की भूमिका की जाँच करें।
4. कृषि में ई-प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने में ई-एनएएम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और ड्रोन के उपयोग जैसी सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। उनकी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें।
5. कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और विश्वास बढ़ाने के लिए कृषि में ब्लॉकचेन तकनीक की क्षमता पर चर्चा करें।
6. कृषि में ई-प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियों, जैसे डिजिटल साक्षरता अंतराल, बुनियादी ढांचे की सीमाएं और सामर्थ्य संबंधी मुद्दों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान सुझाएँ।
7. विभिन्न देशों में कृषि में ई-प्रौद्योगिकी के उपयोग की तुलना करें और अंतर बताएं। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
8. किसानों के बीच ई-प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने और आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में कृषि अनुसंधान संस्थानों और विस्तार सेवाओं की भूमिका पर चर्चा करें।
9. किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पर ई-प्रौद्योगिकी के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करें। प्रौद्योगिकी किसानों को कैसे सशक्त बना सकती है और उनकी आय सुरक्षा में सुधार कर सकती है?
10. डेटा गोपनीयता, पहुंच असमानता और संभावित नौकरी विस्थापन जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए कृषि में ई-प्रौद्योगिकी के नैतिक और सामाजिक निहितार्थों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

बिहार विशिष्ट:

11. बिहार में कृषि में ई-प्रौद्योगिकी अपनाने की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें। ई-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई विशिष्ट पहल और किसानों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें।
12. ई-प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों और सेवाओं तक पहुंचने और उनका उपयोग करने में बिहार में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करें। बाधाएँ क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?
13. बिहार में विशिष्ट ई-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की क्षमता का विश्लेषण करें, जैसे बाजार पहुंच के लिए ई-एनएएम, बेहतर पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और सटीक कृषि के लिए ड्रोन।
14. स्थान-विशिष्ट ई-प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने और किसानों के बीच उन्हें अपनाने को बढ़ावा देने में बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करें।
15. बिहार में कृषि में ई-प्रौद्योगिकी को अपनाने की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सुधार कर सकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।
16. बिहार में कृषि में ई-प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ाने और किसानों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए ठोस नीतिगत उपाय और पहल सुझाएं।
17. बिहार में किसानों को ई-प्रौद्योगिकी अपनाने और तकनीकी सहायता प्रदान करने में गैर सरकारी संगठनों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका का विश्लेषण करें।
18. बिहार में कृषि विपणन परिदृश्य पर ई-प्रौद्योगिकी के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। बाजार की पारदर्शिता में सुधार, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति और फसल के बाद के नुकसान को कम करने की इसकी क्षमता पर चर्चा करें।
19. बिहार में किसानों को ई-प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की आवश्यकता की जांच करें।
20. नवीन ई-प्रौद्योगिकी समाधान सुझाएं जो बिहार के सामने आने वाली विशिष्ट कृषि चुनौतियों, जैसे भूमि विखंडन, सीमित सिंचाई सुविधाओं और मौसम की जानकारी तक पहुंच की कमी का समाधान कर सकें।

❑❑❑

8. खाद्य सुरक्षा

भारत:

1. खाद्य सुरक्षा और इसके विभिन्न आयामों को परिभाषित करें। भारत में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें, इसकी ताकत और कमजोरियों पर प्रकाश डालें।
2. गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और कृषि उत्पादकता चुनौतियों सहित खाद्य असुरक्षा में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें।
3. भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों और नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीडीएस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
4. खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका का विश्लेषण करें, जैसे सटीक कृषि, सूखा प्रतिरोधी फसल की किस्में और फसल कटाई के बाद की तकनीकें।
5. विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के तरीकों की तुलना करें और अंतर बताएं। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
6. भारत में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव पर चर्चा करें और लचीलापन बनाने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए रणनीतियों का सुझाव दें।
7. वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। वैश्वीकृत खाद्य प्रणालियों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें।
8. भूमि और जल संसाधनों तक पहुंच, कृषि उपज का उचित मूल्य निर्धारण और भोजन के समान वितरण जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए खाद्य सुरक्षा नीतियों के नैतिक और सामाजिक निहितार्थों की जांच करें।
9. जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और संसाधनों की कमी जैसी खाद्य सुरक्षा के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन दृष्टिकोण और नीतिगत सिफारिशें सुझाएं।
10. खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने में नागरिक समाज संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर चर्चा करें।

बिहार विशिष्ट:

11. खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में बिहार के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का विश्लेषण करें, जिनमें गरीबी, भूमि विखंडन, सीमित सिंचाई सुविधाएं और वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता शामिल हैं।
12. राज्य में खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार सरकार की पहल, जैसे सात निश्चय और कृषि रोड मैप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
13. बिहार में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और इसकी आबादी की पोषण स्थिति में सुधार लाने में लीची, आम और मक्का जैसी विशिष्ट फसलों की क्षमता पर चर्चा करें।
14. बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन की भूमिका की जांच करें।
15. बिहार में खाद्य सुरक्षा की स्थिति की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सुधार कर सकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।
16. बिहार में खाद्य असुरक्षा को दूर करने और सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतिगत उपाय और पहल सुझाएं।
17. बेहतर कृषि पद्धतियों और बाजार पहुंच के माध्यम से बिहार में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका का विश्लेषण करें।
18. बिहार में खाद्य सुरक्षा पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें और बेहतर लक्ष्यीकरण और दक्षता के लिए सुधार का सुझाव दें।
19. बिहार में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को संबोधित करने में सामाजिक सुरक्षा जाल और पोषण कार्यक्रमों की क्षमता की जांच करें।
20. बिहार में आबादी के बीच खाद्य सुरक्षा प्रथाओं और स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने में शिक्षा और जागरूकता अभियानों की भूमिका पर चर्चा करें।

❑❑❑

9. गरीबी और बेरोजगारी

भारत :

1. गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को परिभाषित करें और उसका विश्लेषण करें। गरीबी की मात्रा निर्धारित करने के विभिन्न उपायों और उनकी सीमाओं पर चर्चा करें।
2. व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर गरीबी के प्रभाव का मूल्यांकन करें। गरीबी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों पर चर्चा करें।
3. गरीबी के जटिल कारणों का विश्लेषण करें, जिसमें संसाधनों का असमान वितरण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी और भेदभाव और सामाजिक गतिशीलता की कमी जैसे संरचनात्मक कारक शामिल हैं।

4. भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और नीतियों, जैसे मनरेगा, पीएम-किसान और उज्ज्वला योजना की प्रभावशीलता पर चर्चा करें।
5. गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका की जांच करें। गरीबों को सशक्त बनाने में मोबाइल प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की क्षमता पर चर्चा करें।
6. विभिन्न देशों में गरीबी कम करने के तरीकों की तुलना करें और अंतर बताएं। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
7. समावेशी विकास की अवधारणा और गरीबी कम करने में इसकी प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें।
8. गरीबी और बेरोजगारी के बीच संबंध का विश्लेषण करें। बेरोजगारी गरीबी में कैसे योगदान करती है और इसके विपरीत?
9. विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी, उनके कारणों और रोजगार खोजने में महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों जैसे विभिन्न समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।
10. बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, जैसे कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार सृजन योजनाएं और उद्यमिता प्रोत्साहन।

बिहार विशिष्ट:

11. बिहार में गरीबी की सीमा और गंभीरता का विश्लेषण करें। राज्य में गरीबी में योगदान देने वाले कारकों, जैसे भूमि विखंडन, सिंचाई सुविधाओं की कमी और सीमित रोजगार के अवसरों पर चर्चा करें।
12. बिहार सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, जैसे- सात निश्चय और जल-जीवन-हरियाली मिशन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
13. बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी कम करने में कृषि, पर्यटन और विनिर्माण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों की क्षमता पर चर्चा करें।
14. बिहार में शिक्षित युवाओं के सामने उपयुक्त रोजगार खोजने में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण करें। रोजगार क्षमता में सुधार और शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी के मुद्दे के समाधान के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।
15. बिहार में गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सुधार कर सकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।
16. बिहार में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतिगत सिफारिशें और पहल सुझाएं।
17. बिहार में गरीबी उन्मूलन और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण करें।
18. बिहार में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पर माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
19. युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करने और सभ्य नौकरियों तक उनकी पहुंच में सुधार करने के लिए बिहार में शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा करें।
20. बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सामाजिक उद्यमिता और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने की क्षमता की जांच करें।

❑❑❑

10. समावेशी विकास

भारत:

1. समावेशी विकास और इसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करें। इसे पारंपरिक आर्थिक विकास मॉडल से अलग करें।
2. समावेशी विकास को बढ़ावा देने के पीछे के तर्क का विश्लेषण करें। सतत विकास प्राप्त करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में इसके महत्व पर चर्चा करें।
3. आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों सहित समावेशी विकास के विभिन्न आयामों की जाँच करें। असमानता को दूर करने और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के महत्व पर चर्चा करें।
4. भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी नीतियों और पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, जैसे सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा जाल और ग्रामीण विकास योजनाएं।
5. समावेशी विकास को बढ़ावा देने में तकनीकी प्रगति की भूमिका पर चर्चा करें। हाशिये पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है?
6. विभिन्न देशों में समावेशी विकास के दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।

7. समावेशी विकास को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों, जैसे लगातार असमानता, सामाजिक बहिष्कार और संसाधनों तक सीमित पहुंच का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
8. समावेशी विकास को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण करें।
9. समावेशी विकास में तेजी लाने और आर्थिक विकास के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए नवीन दृष्टिकोण और नीतिगत सिफारिशें सुझाना।
10. समावेशी विकास पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव पर चर्चा करें और लचीलापन बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों का सुझाव दें।

बिहार विशिष्ट:

11. बिहार में समावेशी विकास की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें। गरीबी, असमानता को कम करने और सामाजिक संकेतकों में सुधार लाने में हुई प्रगति पर चर्चा करें।
12. सात निश्चय और कृषि रोड मैप जैसी समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार की पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
13. बिहार में उन विशिष्ट क्षेत्रों या पहलों की पहचान करें जिन्होंने समावेशी विकास में योगदान दिया है और उनकी सफलता की कहानियों पर चर्चा करें।
14. बिहार में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण समुदायों जैसे आर्थिक और सामाजिक समावेशन को प्राप्त करने में विशिष्ट समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करें।
15. समावेशी विकास के मामले में बिहार के प्रदर्शन की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सुधार कर सकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।
16. समावेशी वृद्धि और विकास को और बढ़ाने के लिए बिहार के लिए विशिष्ट ठोस नीतिगत उपायों और पहलों का सुझाव दें।
17. ग्रामीण बिहार में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका का विश्लेषण करें।
18. बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
19. बिहार में युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा करें।
20. बिहार में समावेशी विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने में योगदान देने में सामाजिक उद्यमिता और छोटे व्यवसायों की क्षमता की जांच करें।

❑❑❑

11. नीति आयोग और उसकी पहल

भारत:

1. अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग की भूमिका और कार्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। उनके दृष्टिकोण और उद्देश्यों में मुख्य अंतर क्या हैं?
2. भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन करने में 15-वर्षीय विजन दस्तावेज, 7-वर्षीय रणनीति पत्र और 3-वर्षीय कार्य एजेंडा जैसी नीति आयोग की पहलों के महत्व पर चर्चा करें।
3. भारत की विकास प्रक्रिया में सहकारी संघवाद और हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देने में नीति आयोग के प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
4. पर्यावरण-अनुकूल और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने में नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक जैसी पहलों के प्रभाव का विश्लेषण करें।
5. अन्य देशों के समान संस्थानों के साथ नीति आयोग की भूमिका और कार्यों की तुलना करें और अंतर बताएं। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
6. नीति आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे संसाधन की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और कार्यान्वयन अंतराल का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इन चुनौतियों से निपटने और इसकी प्रभावशीलता में सुधार करने के तरीके सुझाएं।
7. नीति आयोग के कामकाज और जटिल विकास चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े डेटा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संभावित प्रभाव पर चर्चा करें।
8. नवीन नीति समाधान तैयार करने और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने में नीति आयोग के थिंक टैंक और ज्ञान केंद्रों की भूमिका का विश्लेषण करें।
9. क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और भौगोलिक रूप से वंचित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में नीति आयोग के प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
10. सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने और सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में नीति आयोग की भूमिका पर चर्चा करें।

बिहार विशिष्ट:

11. बिहार के विकास पथ पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम और अटल इनोवेशन मिशन जैसी नीति आयोग की पहलों के प्रभाव का विश्लेषण करें।
12. राज्य के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों, जैसे गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी ढांचे की बाधाओं से निपटने में बिहार सरकार के साथ नीति आयोग के सहयोग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

13. बिहार में बेरोजगारी को दूर करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में कौशल भारत मिशन और स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम जैसी नीति आयोग की पहल की क्षमता पर चर्चा करें।
14. विकास परिणामों के संदर्भ में अन्य आकांक्षी जिलों के साथ बिहार के प्रदर्शन की तुलना करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार ने प्रगति की है और जिन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।
15. राज्य के विकास को और गति देने और इसकी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस नीतिगत सिफारिशें और पहल सुझाएं जिन्हें नीति आयोग बिहार सरकार के सहयोग से लागू कर सके।
16. बिहार के विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने में नीति आयोग की भूमिका का विश्लेषण करें।
17. बिहार में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने में नीति आयोग के प्रयासों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
18. बिहार में डिजिटल विभाजन को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जैसी नीति आयोग की पहल की क्षमता पर चर्चा करें।
19. बिहार की विकास प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और राज्य में निवेश आकर्षित करने में नीति आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करें।
20. बिहार में अपनी पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नीति आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे समन्वय की कमी, क्षमता की कमी और राजनीतिक प्रतिरोध का विश्लेषण करें।

❑❑❑

12. सरकारी बजट और जीएसटी

भारत:

सरकारी बजटिंग:

1. सरकारी बजटिंग की अवधारणा और आर्थिक प्रबंधन में इसके महत्व को परिभाषित करें। विभिन्न प्रकार के बजट और उनकी भूमिकाएँ समझाइये।
2. सुदृढ़ सरकारी बजटिंग के प्रमुख सिद्धांतों, जैसे व्यापकता, पारदर्शिता, जवाबदेही और राजकोषीय जिम्मेदारी का विश्लेषण करें।
3. बजट निर्माण, अनुमोदन, निष्पादन और लेखापरीक्षा सहित बजटीय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें।
4. सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न राजकोषीय नीति उपकरणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, जैसे घाटे का वित्तपोषण, कराधान और व्यय पैटर्न।
5. भारत की बजटीय प्रणालियों की तुलना अन्य देशों से करें। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
6. सरकारी बजटिंग में आने वाली चुनौतियों, जैसे राजस्व में कमी, व्यय दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
7. सरकारी बजटिंग, जैसे ई-बजट और बड़े डेटा विश्लेषण पर तकनीकी प्रगति के संभावित प्रभाव पर चर्चा करें।
8. सरकार के वित्त के प्रबंधन और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में वित्त आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का विश्लेषण करें।
9. सरकारी बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसमें ठोस सुधार और सुधार का सुझाव दें।
10. सरकारी बजटिंग में नैतिक विचारों और जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के महत्व पर चर्चा करें।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी):

11. जीएसटी की अवधारणा और भारत में इसके कार्यान्वयन के औचित्य की व्याख्या करें। जीएसटी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें।
12. भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण करें, जिसमें मुद्रास्फीति, कर संग्रह और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव शामिल है।
13. जीएसटी के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, जैसे अनुपालन मुद्दे, तकनीकी गड़बड़ियां और कर संरचना की जटिलता का मूल्यांकन करें।
14. भारत की जीएसटी व्यवस्था की तुलना अन्य देशों से करें। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
15. जीएसटी अनुपालन और प्रशासन पर ई-वे बिल प्रणाली और अन्य तकनीकी प्रगति के संभावित प्रभाव पर चर्चा करें।
16. कर संरचना को सुसंगत बनाने, अनुपालन मुद्दों को संबोधित करने और जीएसटी शासन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में जीएसटी परिषद की भूमिका का विश्लेषण करें।
17. भारत में जीएसटी कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार के लिए ठोस उपाय सुझाएं।
18. अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे विनिर्माण, कृषि और सेवाओं पर जीएसटी के प्रभाव की जांच करें।
19. जीएसटी क्षतिपूर्ति तंत्र और राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर इसके प्रभाव के संबंध में चिंताओं पर चर्चा करें।
20. भारत में एक साझा बाजार को बढ़ावा देने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में जीएसटी की क्षमता का विश्लेषण करें।

बिहार विशिष्ट:

सरकारी बजटिंग:

21. राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में बिहार सरकार की बजट प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
22. बिहार सरकार को अपने वित्त प्रबंधन में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सीमित संसाधन, उच्च ऋण स्तर और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता का विश्लेषण करें।
23. बिहार के वित्तीय प्रबंधन में सुधार और सतत विकास हासिल करने के लिए विशिष्ट सुधारों और पहलों का सुझाव दें।
24. बिहार के बजटीय प्रदर्शन की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सुधार कर सकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।
25. बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में पीपीपी और सामाजिक प्रभाव बांड जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्र की क्षमता पर चर्चा करें।

जीएसटी:

26. बिहार के राजस्व संग्रह और राजकोषीय समेकन प्रयासों पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण करें।
27. जीएसटी व्यवस्था के अनुपालन में बिहार में व्यवसायों और व्यापारियों के सामने आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करें।
28. बिहार में व्यवसायों और नागरिकों के बीच जीएसटी अनुपालन और जागरूकता में सुधार के लिए विशिष्ट उपाय सुझाएं।
29. बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने में जीएसटी की क्षमता पर चर्चा करें।
30. अपने राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी शासन का लाभ उठाने में बिहार सरकार की भूमिका का विश्लेषण करें।

❑❑❑

13. वर्तमान स्थिति, पिछड़ेपन के कारण और औद्योगिक क्षेत्र में पहल

भारत:

वर्तमान स्थिति:

1. भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें, इसकी विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और ताकत और कमजोरी के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालें।
2. अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन की तुलना करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां भारत उत्कृष्ट है और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां वह पीछे है।
3. अवसरों और चुनौतियों दोनों सहित भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के प्रभाव पर चर्चा करें।
4. औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को आकार देने में बुनियादी ढांचे, श्रम बाजार की स्थितियों और सरकारी नीतियों जैसे विभिन्न कारकों की भूमिका का विश्लेषण करें।

पिछड़ेपन के कारण:

5. भारतीय औद्योगिक परिदृश्य में कुछ क्षेत्रों के पिछड़ेपन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करें।
6. कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में बाधा डालने में ऐतिहासिक कारकों, भौगोलिक बाधाओं और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की भूमिका की जांच करें।
7. पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास पर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल की कमी और वित्त तक सीमित पहुंच के प्रभाव का विश्लेषण करें।
8. कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए नौकरशाही बाधाओं, जटिल नियामक ढांचे और राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें।

पहल:

9. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), औद्योगिक क्लस्टर और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) जैसे पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
10. पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका का विश्लेषण करें।
11. औद्योगिक विकास को गति देने और पिछड़े क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता पर चर्चा करें।
12. क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और भारत में समावेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतिगत सिफारिशें और पहल सुझाएं।

बिहार विशिष्ट:

13. बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, इसकी विकास दर, प्रमुख उद्योगों और प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करें।
14. बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार को सुधार की जरूरत है।
15. बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन में योगदान देने वाले विशिष्ट कारकों की जाँच करें।
16. औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार की सात निश्चय और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जैसी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

17. बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने में कृषि-प्रसंस्करण, कपड़ा और पर्यटन जैसे विशिष्ट उद्योगों की क्षमता पर चर्चा करें।
18. निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बिहार के लिए विशिष्ट ठोस नीतिगत सिफारिशें और पहल का सुझाव दें।
19. बिहार में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निवेश को सुविधाजनक बनाने में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए) और अन्य एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण करें।
20. बिहार में उद्योग स्थापित करने और संचालित करने में उद्यमियों और व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।
21. बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की क्षमता की जांच करें।
22. औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के तरीके सुझाएं।

❑❑❑

14. औद्योगिक नीति, मेक इन इंडिया और एमएसएमई

औद्योगिक नीतिः

1. स्वतंत्रता के बाद से भारत में औद्योगिक नीति के विकास का विश्लेषण करें, प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों और क्षेत्र पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालें।
2. वर्तमान औद्योगिक नीति के उद्देश्यों पर चर्चा करें और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
3. अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की औद्योगिक नीतियों की तुलना करें और अंतर बताएं। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
4. औद्योगिक नीति को आकार देने और लागू करने में सरकार, उद्योग और नागरिक समाज जैसे विभिन्न हितधारकों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
5. गतिशील और वैश्वीकृत वातावरण में प्रभावी औद्योगिक नीतियों को तैयार करने और लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

मेक इन इंडियाः

6. मेक इन इंडिया पहल के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें। भारत में निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
7. रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निर्यात वृद्धि सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर मेक इन इंडिया के प्रभाव पर चर्चा करें।
8. मेक इन इंडिया को प्रभावी ढंग से लागू करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करें, जैसे बुनियादी ढांचे की बाधाएं, नौकरशाही बाधाएं और कौशल अंतराल।
9. मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने और इसकी पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए ठोस सिफारिशें और नीतिगत उपाय सुझाएं।
10. मेक इन इंडिया पहल की तुलना अन्य देशों द्वारा कार्यान्वित समान पहलों से करें। भारतीय दृष्टिकोण की प्रमुख शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करें।

एमएसएमईः

11. भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के महत्व और सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में उनके योगदान का विश्लेषण करें।
12. एमएसएमई के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करें, जैसे वित्त तक पहुंच, तकनीकी प्रगति और बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा।
13. एमएसएमई की वृद्धि और विकास को समर्थन देने में सरकारी नीतियों और पहलों की भूमिका पर चर्चा करें।
14. एमएसएमई को सशक्त बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में मुद्रा ऋण, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
15. भारत में एमएसएमई के विकास और स्थिरता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नवीन दृष्टिकोण और नीति सुधारों का सुझाव दें।

बिहार विशिष्टः

16. बिहार सरकार की औद्योगिक नीति और राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के साथ इसके संरेखण का परीक्षण करें।
17. बिहार के औद्योगिक परिदृश्य पर मेक इन इंडिया के प्रभाव का मूल्यांकन करें, निवेश आकर्षित करने और विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें।
18. बिहार में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों और उन चुनौतियों से निपटने में सरकारी पहल की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें।
19. बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपायों और पहलों का सुझाव दें।
20. बिहार में एमएसएमई क्षेत्र के विकास की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सीख सकता है और सुधार कर सकता है।

❑❑❑

15. उद्योगों में निजीकरण एवं उदारीकरण की भूमिका

निजीकरण:

1. निजीकरण को परिभाषित करें और भारतीय आर्थिक संदर्भ में इसके औचित्य और उद्देश्यों पर चर्चा करें।
2. निजीकरण के विभिन्न तरीकों, जैसे विनिवेश, संपत्तियों की बिक्री और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का विश्लेषण करें।
3. सरकार, निजी क्षेत्र, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों पर निजीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
4. भारत के निजीकरण के अनुभवों की तुलना अन्य देशों से करें। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।
5. निजीकरण को प्रभावी ढंग से लागू करने में आने वाली चुनौतियों, जैसे राजनीतिक प्रतिरोध, नियामक बाधाएँ और मूल्यांकन के मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

उदारीकरण:

6. आर्थिक उदारीकरण की अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार में इसके महत्व की व्याख्या करें।
7. भारत में उदारीकरण के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करें, जिसमें व्यापार उदारीकरण, औद्योगिक विनियमन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सुधार शामिल हैं।
8. कृषि, उद्योग और सेवाओं सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उदारीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करें।
9. भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास संकेतकों पर उदारीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
10. भारत के उदारीकरण अनुभवों की अन्य देशों से तुलना करें। भारत के लिए सीखे गए प्रमुख सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करें।

निजीकरण और उदारीकरण के बीच अंतरसंबंध:

11. निजीकरण और उदारीकरण के बीच संबंध और भारतीय औद्योगिक परिदृश्य पर उनके संयुक्त प्रभाव का परीक्षण करें।
12. विश्लेषण करें कि कैसे निजीकरण और उदारीकरण ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा, दक्षता में सुधार और औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद की है।
13. राजस्व सृजन और राजकोषीय घाटे में कमी सहित सार्वजनिक वित्त पर निजीकरण और उदारीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
14. निजीकरण और उदारीकरण से जुड़े संभावित जोखिमों और चुनौतियों पर चर्चा करें, जैसे नौकरी का नुकसान, बाजार की शक्ति का संकेंद्रण और सामाजिक असमानता।
15. निजीकरण और उदारीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और समावेशी और टिकाऊ औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दें।

❑❑❑

16. बुनियादी ढांचा

भारत:

1. बुनियादी ढांचे को परिभाषित करें और आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें।
2. भारत में बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें, ताकत और कमजोरी के क्षेत्रों पर प्रकाश डालें।
3. अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के बुनियादी ढांचे के विकास स्तरों की तुलना करें और अंतर बताएं।
4. भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करें, जैसे कि धन की कमी, नौकरशाही बाधाएं और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे।
5. बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर चर्चा करें।

विशिष्ट क्षेत्र:

6. भारत में परिवहन (सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे), ऊर्जा (बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन), जल और स्वच्छता और डिजिटल बुनियादी ढांचे सहित विशिष्ट बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें।
7. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), सागरमाला परियोजना और भारतमाला परियोजना जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
8. बुनियादी ढांचे के विकास में परिवर्तन लाने में स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों की क्षमता पर चर्चा करें।
9. प्रत्येक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस नीतिगत सिफारिशें और पहल सुझाएं।

वित्तपोषण बुनियादी ढाँचा:

10. सार्वजनिक निधि, निजी क्षेत्र के निवेश और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण संस्थानों सहित बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण करें।
11. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका पर चर्चा करें।
12. विभिन्न वित्तपोषण तंत्रों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें और भारत में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में सुधार के तरीके सुझाएं।

13. सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश आकर्षित करने में बुनियादी ढांचा बांड और हरित बांड जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्र की क्षमता पर चर्चा करें।

सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव:

14. विस्थापन, संसाधन की कमी और प्रदूषण जैसे मुद्दों सहित बुनियादी ढांचे के विकास के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करें।
15. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में स्थिरता सिद्धांतों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल करने के महत्व पर चर्चा करें।
16. बुनियादी ढांचे के विकास के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दें।

बिहार विशिष्ट:

17. बिहार में बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें, उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालें जहां यह राष्ट्रीय औसत से पीछे है।
18. बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार सरकार की सात निश्चय और बिहार विजन 2030 जैसी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
19. उन विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करें जो बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के तरीके सुझाएं।
20. बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार को सुधार की आवश्यकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण किया जा सकता है।

❑❑❑

17. विदेश व्यापार

भारत:

1. विदेशी व्यापार की अवधारणा और आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए इसके महत्व की व्याख्या करें।
2. भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें, जिसमें इसके प्रमुख व्यापारिक भागीदार, निर्यात और आयात संरचना और समग्र व्यापार संतुलन शामिल हैं।
3. अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के विदेशी व्यापार पैटर्न की तुलना करें और अंतर बताएं।
4. भारत के विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों, जैसे व्यापार नीतियां, टैरिफ, विनिमय दरें और वैश्विक आर्थिक स्थिति की पहचान करें।
5. भारत के विदेशी व्यापार पर मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) जैसे विभिन्न व्यापार समझौतों के प्रभाव पर चर्चा करें।

विशिष्ट विषय:

6. कृषि, विनिर्माण और सेवाओं जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अपने निर्यात को बढ़ाने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करें।
7. व्यापार घाटे से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करें और इसे कम करने के लिए रणनीतियाँ सुझाएँ।
8. निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की पहल की प्रभावशीलता की जांच करें, जैसे 'मेक इन इंडिया' अभियान और भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एमईआईएस)।
9. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकी प्रगति के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
10. वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने और व्यापार विवादों को सुलझाने में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की क्षमता पर चर्चा करें।

बिहार विशिष्ट:

11. बिहार की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार के योगदान का विश्लेषण करें।
12. बिहार में विशिष्ट निर्यात संभावित क्षेत्रों की पहचान करें और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के तरीके सुझाएं।
13. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार की पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
14. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने में बिहार के व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।
15. बिहार के विदेशी व्यापार प्रदर्शन की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां बिहार सुधार कर सकता है और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।

❑❑❑